भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2024 के

अतारांकित प्रश्न सं. 424 का उत्तर

पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार

424. श्री दिलीप शइकीया:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में नई रेलवे लाइन के निर्माण से संबंधित कितनी परियोजनाएं चल रही हैं तथा उनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान देश में क्रियान्वित रेलवे परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने असम के दारंग जिले को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए कोई ठोस कदम उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

s.k

पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के संबंध में दिनांक 27.11.2024 को लोक सभा में श्री दिलीप शइकीया के अतारांकित प्रश्न सं. 424 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति/निष्पादन क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है न कि राज्य/जिला-वार/क्षेत्र-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित भारतीय रेल की लगभग 7.44 लाख करोड़ रू. की लागत वाली कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की कुल 488 रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं (187 नई लाइन, 40 आमान परिवर्तन और 261 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरण में हैं, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई को कमीशन किया गया है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रू. का व्यय किया गया है।

भारतीय रेल में नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण के लिए औसत वार्षिक बजट आवंटन इस प्रकार है:-

अवधि	बजट परिव्यय	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	11,527 करोड़ रु. प्रति वर्ष	-
2024-25	68,634 करोड़ रु. प्रति वर्ष	लगभग 6 गुना

s.k

भारतीय रेल में नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण की कमीशनिंग का ब्यौरा इस प्रकार है:-

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई	2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	7,599 किलोमीटर	4.2 किलोमीटर/दिन	-
2014-24	31,180 किलोमीटर	8.54 किलोमीटर/दिन	2 गुना से अधिक

2023-24 में, भारतीय रेल में 5,309 किलोमीटर खंड को कमीशन किया गया है।

सभी रेल परियोजनाओं की लागत, व्यय और परिव्यय सहित क्षेत्र-वार/वर्ष-वार विवरण भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान अर्थात वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2023-24 तक, भारतीय रेल में कुल 23,352 किलोमीटर लंबाई की 297 परियोजनाओं (नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) को पूरा किया गया, जिनकी लागत लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेल अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भारतीय रेल की पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (पू.सी.रे) क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।

दिनांक 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 74,972 करोड़ रू. की लागत वाली कुल 1,368 किलोमीटर लंबाई की 18 परियोजनाएं (13

नई लाइनें और 5 दोहरीकरण) योजना/अनुमोदन/निर्माण के चरण में हैं, जिनमें से 313 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च 2024 तक 40,549 करोड़ रूपए का व्यय किया जा चुका है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यो के लिए औसत बजट आवंटन इस प्रकार है:-

अवधि	बजट परिव्यय	2009-14 के औसत आबंटन की तुलना में वृद्धि
2009-14	2,122 करोड़ रू./वर्ष	-
2014-24	10,376 करोड़ रू.	लगभग 5 गुना

इसके अतिरिक्त, 2009-14 और 2014-24 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाले खंडों (नई लाइनें, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण) की कमीशनिंग निम्नानुसार है:

अवधि	कमीशन की गई कुल लंबाई	कमीशन की गई औसत लंबाई	वर्ष 2009-14 के दौरान औसत कमीशनिंग की तुलना में वृद्धि
2009-14	333 किलोमीटर	66.6 किलोमीटर प्रति वर्ष	-
2014-24	1,728 किलोमीटर	172.8 किलोमीटर प्रति वर्ष	लगभग 2.6 गुना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल 110 कि.मी. की कमीशनिंग की गई है।

s.k

किसी भी परियोजना का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, लागत में हिस्सेदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत हिस्से की राशि को जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति के कारण परियोजना विशेष के स्थान के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

असम के दरांग जिले से गुजरने वाली अगठोरी-डेकरगांव (155 कि.मी.) नई रेल लाइन के लिए अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।

*****

s.k